24 घंटे में खाते में चली जाएगी मनरेगा की मजदूरी

हिन्दुस्तान
खास

पटना | **कौशिक रंजन**

मनरेगा में मजदूरी भुगतान में देरी और इससे जुड़ी गड़बड़ी के सबसे ज्यादा मामले सामने आते हैं। बड़ी संख्या में मिलने वाली ऐसी शिकायतों को दूर करने के लिए ग्रामीण विकास विभाग ने ई-एफएमएस (इलेक्ट्रॉनिकल- फंड मैनेजमेंट सिस्टम) नई प्रणाली विकसित की है। इस नई प्रणाली के जरिये मजदूरों के बैंक या पोस्ट ऑफिस एकाउंट में चौबीस घंटे के अंदर सीधे मजदूरी के रुपये पहुंच जाएंगे।

फिलहाल इस नई प्रणाली का उपयोग सिर्फ मनरेगा की मजदूरी भुगतान में शुरू किया गया है। आने वाले दिनों में इसे मनरेगा से जुड़े सामानों के भुगतान, कर भुगतान, इंदिरा आवास योजना समेत अन्य में भी लागू करने की योजना है। इस प्रणाली का सफल प्रयोग जहानाबाद के कुर्था प्रखंड में किया जा चुका है।

ये फायदे होंगे इससे

इसकी अवधारणा है, 'राइट एमाउंट टू राइट वेनिफिशियरी' वह भी कम से कम समय में। इसमें पीओ से लेकर तमाम स्तर के पदाधिकारियों की दखलअंदाजी खत्म हो जाएगी। कम मजदूरी का भुगतान, गलत व्यक्ति को भुगतान, किसी का पैसे किसी के नाम पर भुगतान, मजदूरी देने में देरी, मजदूरी भुगतान में बिचौलियों की दखलअंदाजी, कमीशनखोरी समेत तमाम ऐसी गड़बड़ियां दूर हो जाएंगी। मस्टर रोल में गड़बड़ी की आशंका भी दूर होगी। अब हर मनरेगा मजदूर का खाता उसके नाम से खुलेगा। अगर किसी परिवार में कई लोग हैं, तो सभी का अलग-अलग खाता होगा या उस परिवार का संयुक्त खाता खोला जाएगा। फंड का प्रबंधन सही तरीके से हो सकेगा। पदाधिकारियों की जवाबदेही बढ़ेगी।

नई प्रणाली से होगा भुगतान

- इस वर्ष अंत तक सभी जिलों में शुरू होगा ई-एफएमएस
- मनरेगा की मजदूरी सीधे लोगों के एकाउंट में होगा ट्रांसफर
- भुगतान में पीओ से लेकर तमाम अफसरों की दखलअंदाजी खत्म
- अरवल के कुर्था प्रखंड में हुआ इसका सफल क्रियान्वयन

विभाग ने इस प्रणाली को दो जिलों जहानाबाद और किशनगंज में शुरू किया है। इस वर्ष के अंत तक सभी जिलों में ई-एफएमएस के माध्यम से पेमेंट की व्यवस्था कर दी जाएगी। जो लगातार काम करने वाले मजदूर हैं, उनके जॉब कार्ड का वेरिफिकेशन करवाकर खाता खुलवाया जा रहा है। इसकी तैयारी पहले से ही की जा रही थी, लेकिन अब इसे पूरी तरह लागू किया जा रहा है।

अमृत लाल मीणा (सचिव, ग्रामीण विकसा विभाग)

ऐसे काम करेगी यह प्रणाली

जो मजदूरी करेंगे, उनके खाता में विभाग आरटीजीएस (रीयल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट) या एनईएफटी (नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर) के माध्यम से भुगतान करेगा। इसमें किसी तरह की कागजी प्रक्रिया नहीं होगी। रुपए के हस्तांतरण के लिए पीओ या संबंधित पदाधिकारी को इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर करना होगा। इसके लिए लाभुक के पास जाने या उसे कहीं आने-जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ई-एफएमएस की पूरी प्रणाली को यूएनडीपी के सहयोग से विकसित किया गया है। इसे देखने वाले सुनीत अग्रवाल का कहना है कि जो लोग मजदूरी कर रहे हैं, उन्हीं को ही छांटकर खाता खुलवाया गया है। इससे गलत भुगतान या अन्य किसी गड़बड़ी की आशंका नहीं रहती है।